कृषि भूमि की वैश्विक लूट बंद करो!

ग्रेन और अंतरराष्ट्रीय किसान आंदोलन ला विया कैंपेसिना द्वारा संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में ग्रेन द्वारा जारी वक्तव्य

रोम, 16 नवंबर, 2009

http://www.grain.org/o/?id=87

पिछले करीब एक–डेढ़ साल से हम इस बात पर काफी सतर्क निगाह रखे हुए हैं कि खाद्य और वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में दुनिया भर के निवेशक कैसे अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में कृषि भूमि पर नियंत्रण की कोशिशें कर रहे हैं। आरंभ में 2008 के शुरुआती महीनों में वे ''खाद्य सुरक्षा'' के नाम पर इन जमीनों को हड़पने की बात करते थे। खाड़ी देशों के अधिकारियों ने दुनिया भर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था ताकि वे चावल उगाने के लिए जमीनें पहचान सकें जिससे वे अपनी बढ़ती आबादी का पेट भर सकें और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। यही हाल कोरिया, लीबिया, मिस्र आदि का भी था। इन तमाम वार्ताओं में उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी शामिल रहे और राजनीतिक, आर्थिक व वित्तीय सहयोग के नाम पर की गई इन वार्ताओं के केंद्र में दरअसल कृषि भूमि की लेन–देन थी।

जुलाई 2008 आते–आते वित्तीय संकट गहरा गया और हमने देखा कि ''खाद्य सुरक्षा के नाम पर जमीनें हड़पने वालों'' के साथ निवेशकों का एक अन्य समूह भी शामिल हो गया जो दक्षिण में कृषि भूमि पर कब्जे में लगा था : हेज फंड, निजी इक्विटी समूह, निवेश बैंक आदि। वे खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं थे। उन्होंने पहचान लिया था कि खेती से पैसा बनाया जा सकता है क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खाद्यान्न की कीमतें लंबे समय तक वृद्धि की ओर रहेंगी और कृषि भूमि को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इन कृषि भूमि अधिग्रहणों में थोड़ी सी तकनीक और प्रबंधन कौशल लगा कर वे अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर सकते थे जो मुद्रास्फीति के खिलाफ एक हेज का काम करता तथा जिसकी रिटर्न तय होती– पैदावार और जमीन दोनों के मामले में!

अब तक करीब 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन का मालिकाना या तो बदल चुका है या फिर बदलने वाला है– जिसमें अकेले दो करोड़ हेक्टेयर अफ्रीका में है। और हमारी गणना के मुताबिक ऐसा करने के लिए 100 अरब डॉलर से ज्यादा झोंके गए हैं। सतही तौर पर भले ही इसमें सरकारी भूमिका हो, लेकिन अधिकतर समझौते निजी निगमों ने मेजबान देशों के अधिकारियों के साथ मिल कर किए हैं। ग्रेन ने जमीन हड़पने वालों और समझौतों की सूची संकलित की है, लेकिन अधिकतर सूचना को राजनीतिक प्रतिक्रिया के चलते सार्वजनिक नहीं किया गया है।

दक्षिण में कृषि भूमि की इस होड़ में स्थानीय समुदायों के हाथ कुछ नहीं आएगा और उनके हित में कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे आप किसी भी देश को ले लें– पाकिस्तान, कंबोडिया, फिलीपींस, मेडागास्कर, केनिया, सुडान, इथियोपिया या माली। इनमें से कई देशों में खुद भयंकर खाद्य असुरक्षा है। यहां सारी जमीनें इसलिए हड़पी जा रही हैं ताकि छोटे स्तर की खेती को विदा कह दिया जाए। यही इकलौती वजह है कि दुनिया भर के सामाजिक आंदोलन कृषि भूमि की इस वैश्विक लूट को जबर्दस्त संघर्ष का आधार मान रहे हैं– न सिर्फ भूमि को लेकर, बल्कि पानी के मुद्दे पर भी।

आज रोम में हमें इस संघर्ष का सूक्ष्म रूप दिख जाएगा। एफएओ में सरकारें, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जैसे विश्व बैंक और निजी कंपनियां (यारा, बुंजे, ड्रेफस) आदि एक ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसे वे आचार संहिता या स्वैच्छिक दिशानिर्देश कहते हैं, जिससे ये समझौते सभी के फायदे के लिए यानी ''विन–विन'' बनाए जा सकें। उनकी वास्तविक चिंता पैसे बनाने की है। वे नहीं चाहते कि डॉलर और दिरहम उनके हाथ से कैसे भी फिसलने पाएं। इसीलिए उन्होंने इन जमीनों के सौदों में शामिल जोखिम को संतुलित करने के लिए मौके का लाभ उठाया है। और हम इसकी वजह जानते हैं। हरित क्रांति और जैव–प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के 50 साल और ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों के 30 साल के बाद आज इस धरती पर पहले से कहीं ज्यादा भूखे लोग हैं। सीधी सी बात है कि दुनिया का पेट भरने के नाम पर बनाए गए ये सभी कार्यक्रम अब विफल हो चुके हैं। विश्व बैंक और दूसरों ने अब तय कर लिया है कि पैसे के पीछे बढ़ा जाए और बड़े पैमाने पर कृषि–औद्योगिक गतिविधियां हर जगह शुरू कर दी जाएं, जहां अब तक वे मौजूद नहीं हैं। यही भूमि लूट के मुहावरे का सत्व है: कि व्यापक स्तर की जिंस मूल्य श्रृंखला के पश्चिमी मॉडल को विस्तार दे दिया जाए। दूसरे शब्दों में निर्यात के लिए ज्यादा कॉरपोरेट नियंत्रण वाला खाद्यान्न उत्पादन!

सामाजिक आंदोलन चीजों को दूसरे नजरिये से देखते हैं। हमारे लिए ''विन–विन'' का यह हल्ला वास्तविक नहीं है। यह पारदर्शिता और सुशासन की बात करता है, जैसे कि विदेशी निवेशक जमीन पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता दे देंगे, जबकि घरेलू सरकारें ही ऐसा नहीं करती हैं। यह नौकरियों और तकनीक हस्तांतरण की बात करता है, जबकि यह समस्या है ही नहीं (और यह बताने की जरूरत नहीं कि दोनों में कोई भी पूरा नहीं होगा)। इसमें 'सुनिश्चित', 'आत्मविश्वास' और 'संकल्प' की जगह 'स्वैच्छिक', 'भय' और 'सकते हैं' जैसे शब्द भरे हुए हैं। और यह ''विन–विन'' खेमा खुद ही इस बात पर विभाजित है कि जब मेजबान देश में खाद्यान्न पर दबाव बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो एक संभावित परिदृश्य है। क्या देशों को विदेशी निवेशकों के फार्मों से भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की छूट मिल सकेगी? या फिर तथाकथित मुक्त व्यापार और निवेशकों के अधिकार हावी हो जाएंगे? हमने एशिया और अफ्रीका में जिनसे भी बात की, उनमें से कोई भी सभी के लिए जीत वाले ''विन–विन'' के मुहावरे को गंभीरता से नहीं लेता।

आज विकासशील देशों में विदेशी निवेशकों द्वारा जमीनों और पानी पर नियंत्रण के परिदृश्य का घरेलू खेती और स्थानीय बाजारों से कोई लेना–देना नहीं है, जबकि यह हमारी नजर में इकलौता ऐसा रास्ता है जो लोगों के पेट भरने के लिए पर्याप्त एक खाद्य प्रणाली को बना सकता है। इसे रोका जाना होगा। इसमें सभी की जीत संभव नहीं, क्योंकि जो निवेशों को आगे बढ़ा रहे हैं, वे सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि ''इन निवेशों को कैसे संभव बनाया जाए?'' सही सवाल है, ''ऐसी कौन सी कृषि और खाद्य प्रणाली है जो लोगों को बीमार किए बगैर, किसानों को शहरी झुग्गियों में धकेलने की बजाय खेतों में बचाए रख कर और समुदायों को समृद्ध कर लोगों का पेट भर सकती है?'' एक बार यदि हम इस पर सहमत हो जाएं कि असली सवाल उस खेती के चरित्र का है जो हम चाहते हैं, तब हम बात कर सकते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए कैसे निवेश की जरूरत होगी।

ग्रेन में हम इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि वैश्विक भूमि की वर्तमान लूट खाद्य संकट को और बदहाल छोड़ देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह खेती को एकफसली, जीएमओ की ओर धकेलती है, मशीनों को लाकर किसानों को खेतों से बाहर कर देती है और इसमें तमाम जीवाश्म ईंधनों और रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह कृषि सबका पेट नहीं भर सकती। यह कुछ लोगों के लिए भारी मुनाफा और बाकी के लिए घोर गरीबी लाती है। जाहिर है निवेश तो होना ही चाहिए, लेकिन वह करोड़ों स्थानीय बाजारों में चार अरब ग्रामीण लोगों की खाद्य संप्रभुता में किया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न उपजाते हैं और जिस पर हमारा समाज निर्भर है– न कि कुछ मुट्ठी भर मेगा फार्मों में, जिन पर कुछेक विशाल भूस्वामियों का कब्जा है।

देखें ग्रेन और विया कैंपेसिना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रणः

http://www.grain.org/m/?id=268

http://farmlandgrab.org

http://www.grain.org/landgrab/

http://peoplesforum2009.foodsovereignty.org/

http://www.fao.org/wsfs/world-summit/en/